













# संपादकीय

# विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र बन चुका है भारत

भारत अब विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन चुका है। मेक इन इंडिया अभियान की मदद से भारत हाई-टेक विनिर्माण का केंद्र बनने की राह पर है। क्योंकि वैश्विक दिग्गज या तो भारत में विनिर्माण संयंत्र लगा रहे हैं या लगावे की प्रक्रिया में हैं, जो भारत के एक अरब से अधिक उपभोक्ताओं के बाजार और उनकी बढ़ती क्रय शक्ति से आकर्षित हैं। ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निगरानी में भारत 1,200 से अधिक सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों, सक्रिय नीति तंत्र, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग के साथ नवाचार अर्थव्यवस्था के युग को लेकर खुद को तैयार कर रहा है। भारत नवाचार के निरंतर बढ़ते पथ पर है और उभरती हुई तकनीकियां जैसे ब्लॉक चेन, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार के केंद्र में हैं। भारत शीर्ष 25 नवोन्मेषी देशों के संघ में शामिल होना चाहता है एनएसएफ डेटाबेस के हिसाब से वैज्ञानिक प्रकाशन के देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) के अनुसार इसने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 नवीन अर्थव्यवस्थाओं में (46वें रैंक पर) जगह बनाई है। इसने पीएचडी की संख्या, उच्च शिक्षा प्रणाली के आकार के साथ-साथ स्टार्ट-अप की संख्या के मामले में भी तीसरा स्थान हासिल किया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, समावेश और पारदर्शिता हासिल करने के लिए तकनीकी को एक माध्यम बनाया है सरकार तकनीकी का उपयोग कर अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करती है। वहीं, डीएसटी लोगों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। वह देश में अनुसंधान व नवाचार अभियान का नेतृत्व कर रहा है इस दिशा में भारत के द्वारा कई पिशान मोड कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जैसे- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, अंतरिक्षयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (आईसीपीएस), क्वांटम कम्प्यूटिंग और संचार, सुपरकम्प्यूटिंग, सुपरकम्प्यूटिंग पर राष्ट्रीय मिशन, इलेक्ट्रिक मौबिलिटी आदि, ताकि इस अभियान का सहयोग किया जा सके। देखा जाए तो पिछले 75 वर्षों में भारत विकासपरक यात्रा से गुजरा है, जिसने इसकी वैश्विक राष्ट्रों के बीच एक अलग आर्थिक और राजनीतिक पहचान बनाने में मदद की है। इसलिए आज जब भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, वह अपने लिए अगले 25 वर्षों के निमित्त रोडमैप @100 तैयार कर रहा है ताकि वर्ष 2047 तक जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक व तकनीकी नवाचारों द्वारा प्रगति हासिल अथवा निर्धारित की जा सके।

# सरयू से संगम तक: यूपी का पांचवा इम्तहान, 12 जिलों की 61 सीटों का पूरा प्लान

पांचवें फेज की जग अयोध्या और प्रयागराज जैसे जिलों में होनी है। जिसके लिए 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीट पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस रण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों से ऐडी-चोटी का जोर लगा दिया है। कल मायावती प्रयागराज में थी तो अखिलेश यादव सुल्तानपुर में दिखे। अमित शाह बाराबंकी से अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चक्रव्यूह के पांचवें द्वार को कौन भेदगा। चौथे चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब पांचवें चरण की लड़ाई तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी और मायावती से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पांचवें चरण के लिए पूरी तात्काल लगा दी है।

पांचवें चरण के लिए यूपी के 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अखिलेश ने जहां अमेठी और सुल्तानपुर में विरोधियों पर हमले बोल रहे थे तो बाराबंकी से भाजपा के चाणक्य अमित शाह एक साथ सपा और बसपा पर गरज रहे थे। मायावती प्रयागराज की सभी 12 सीटों पर हाथी की रफतार बढ़ा रही थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चुनावी रैली की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में कांग्रेस को निशाने पर लिया।

यूपी की इन 12 जिलों में वोटिंग-अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज,

A collage featuring several prominent Indian political figures and flags. On the left, a man in an orange hoodie looks directly at the camera. Next to him is a man in a dark suit and red turban. To the right is a woman in a red sari with a yellow garland, smiling. Further right is another woman in a white sari. The background is filled with various Indian flags, including the Congress party's green and orange flag, the BJP's saffron flag, and the Trinamool Congress's red and green flag. There are also several other smaller flags and political symbols.

बाराबका, अयाध्या, बहराइच, श्रावस्ता, गोंडा  
**2017 में बीजेपी का 90 प्रतिशत रहा**  
था स्टाइक रेट-गैरतलब है कि यूपी की चुनावी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही है। इस रेस में कांग्रेस और बसपा पीछे दिखा दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड़ा पूरा जोर लगा रही है। लेकिन बसपा पर आरोप लग रहे हैं कि मायावती इस चुनाव को ठीक तरीके से नहीं लड़ रही हैं। जिस तरह से उन्हें लड़ना चाहिए क्योंकि प्रयागराज की रैली में भीड़ तो आई लेकिन उनके बयानों में वो आक्रमकता नहीं दिखी जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को पांचवें चरण की जिन 61 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें से करीब 90 फीसदी सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगियों का

पर पहुंचने वाली बीजेपी के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या बड़ा बॉन्ड बन चुका है। यूपी के पांच चरण के चुनावी रण में मयार्दी पुरुषों श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी कर्मभूमि चित्रकूट और प्रयागराज में भी मतदान होगा। 2017 के चुनाव में अयोध्या की सभी पांच सीटों पर भवित्व लहराया था। ज्ञात हो कि प्रभु राम बनवास के करीब 11 साल चित्रकूट व्यतित किए थे जहाँ पिछले चुनाव में सीटों पर कमल खिला था। अयोध्या विकास मॉडल भी योगी के चुनाव प्रकारा अहम हिस्सा बना हुआ है और मंदिर का निर्माण भी पूरे जोर-शोर से चल रहा है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है आधा दर्जन मंत्री की साख दांव पर पांचवें चरण के चुनाव में योगी सरकार के कई दिग्गज मर्तियों की साख दांव के लिए है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मुख्यमंत्री सीट से चुनावी मैदान में हैं वहाँ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। इलाहाबाद की पश्चिम सीट कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद दक्षिण से नागरिक उद्युगी नंद गोपाल नंदी चुनाव लड़ रहे हैं चित्रकूट सदर से चौंकिका प्रसाद उपाध्याय तो वहाँ मनकामना की सुरक्षित सीट समाज कल्याण मंत्री रमापति शांत चुनावी मैदान में हैं।

# कांग्रेस बिना अधूरा ही रहेगा क्षेत्रीय दलों का गठबंधन



अपना सत्ता बढ़ान के लिए दूसरे राज्यों में पहल भा की तो इसमें खास सफलता हाथ नहीं लगी। दूरअस्त्र व्यक्तियों द्वारा की एकजटता में कांग्रेस गले बल्ट सारे भाज़

तक हा उनका राजनातक सामन्त ह। फिर भा क्षेत्रीय दल यदि एक जुट होकर अपना प्रत्याशी पा और कांग्रेस के खिलाफ उतार भी दें तो टिकट वितरण में ही सिर फुटब्लॉक की नौबत जाएगी। प्रत्याशियों को चुनना और उनके लिए बीच खर्च का इंतजाम करना आसान काम नहीं। वर्तमान में ऐसा हो चुका है कि दूसरे राज्यों में कुछ जीतने के बाद क्षेत्रीय दल के विधायक कांग्रेस जापा की झोली में चले गए। ऐसे में कुछ सीटें ने के बावजूद क्षेत्रीय दलों के लिए यह खतरा बना रहेगा।

क्षेत्रीय दलों के गठबंधन में प्रमुख ह क्षेत्रीय दल वाले ही पड़ोसी राज्य भी हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा है। क्षेत्रीय दल अपने पड़ोसी राज्य में अपना विस्तार नहीं होता है। ऐसे में दूसरे क्षेत्रीय दलों से टकराव होना है।

ऐसा अब तक होता भी रहा है। एकता की राह के और बड़ी बाधा चुनावी घोषणा पत्र है। इसमें विधायक करने में सबके अपने-अपने हित है। सिर्फ विधायक पा और कांग्रेस के खिलाफ लिख कर घोषणा भूरा नहीं किया जा सकता है। इतना जरूर है कि गठबंधन चाहे क्षेत्रीय दलों के आधार वाले जखारा और आतंकियों का निरपत्तारा हा चुक ह। इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों का वर्चस्व रहा है। केरल में कम्युनिस्ट और बिहार में लालू यादव के शासन के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कह इबार आर्टिकियों की धरपकड़ की है। सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों के सामने भ्रष्टाचार से निपटना भी प्रमुख चुनौती रही है। इस विषेश का क्षेत्रीय दलों ने मुखर विरोध नहीं किया। अलबत्ता केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की कार्रवाई का पुरजोर विरोध अवश्य किया है। ईडी और सीबीआई की भ्रष्टाचार की कार्रवाई के खिलाफ तो ममता बनर्जी धरने-प्रदर्शन पर उतर आई। इस मुद्दे पर भी इन दलों ने कभी एकराय व्यक्त नहीं की। ममता हो या चंद्रशेखर राव, किसी के लिए भी कांग्रेस को शामिल किए बगैर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाना आसान नहीं है। यदि ऐसा गठबंधन बन भी गया तो वह कांग्रेस के बगैर वह रीढ़विहीन ही होगा।

क्षेत्रीय दलों को देश की एकता-अखंडता के मुद्दे पर अपना नरम रवैया छोड़ना होगा। इसके साथ ही देश के विकास का मजबूत खाका पेश करना होगा। भ्रष्टाचार और विकास के लिए रोडमैप देश के सामने रखना होगा।

# अहमदाबाद ब्लास्ट केसः सबको अपने किये का फल भुगतना पड़ेगा

डा. वंदप्रताप वांदक  
०८ में अहमदाबाद में

— 1 —

# अखिलेश का पलायन-दंगाइयों पर चुप्पी और अब आतंकवाद पर खामोशी



लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने अखिलश को धरने में कोई कोरकसर नहीं रखी। उनाव में प्रधानमंत्री मोदी के तो हार्डेड में योगी के निशाने पर अखिलेश

रहे। उन्नाव में मोदी ने सपा के चुनाव निशान साइकिल को लेकर अखिलेश पर खूब शब्दबाण चलाए। बीजेपी वालों ने गजरात में सीरियल ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले पर तो अखिलेश

का धरा हा इसके अलावा आतंकवाद के बह बद पन भा खोल दिए जिसकी इब्राहिम अखिलेश सरकार के समय तमाम खूबां आतंकवादियों से मुकदम्में वापस लेकर लिखी गई थी। इसी लिए राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि आतंकी हमले के आरोपितों के प्रति सपा द्वारा साप्ट कार्नर अपनाने का भाजपा का आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है। अखिलेश सरकार के दौरान 2013 में सात जिलों में आतंकी हमले से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए गए थे। हालांकि, कुछ मामलों में अदालत के मना करने के बाद आरोपितों को 20-20 साल तक की सजा तक हुई थी। सीएम रहते अखिलेश ने जिन 14 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया था। उनमें लखनऊ के छह और कानपुर के तीन मामले थे। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर, विजनौर, रामपुर और बाराबंकी का एक-एक मामला था। पांच मार्च, 2013 को वाराणसी के जिस मामले को वापस लिया गया था, वह सात मार्च 2006 में संकट मोचन मंदिर एवं रेलवे स्टेशन कैट पर हुए सिलसिलेवार बम धमाके से जुड़ा था। वाराणसी में एक प्रेशर कुकर में घड़ी लगा विस्फोटक



